सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

परिवाद संख्या – 13782/1131/2023

के मामले में—

श्री राकेश कुमार,
ग्राम-सुमली, पोस्ट-बेहटा,
तहसील-लहरपुर, जिला-सीतापुर,
पिन - 261208 (उत्तर प्रदेश) **... परिवादी**

बनाम

(1) मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक
पंजाब नेशनल बैंक, कठूरा शाखा,
ग्राम व पोस्ट – कठूरा,
जिला – सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
पिन – 261208
Email: care@pnb.co.in **... प्रतिवादी संख्या 1**

(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनडीएफडीसी)
यूनिट संख्या 11 एवं 12, भूतल,
डीएलएफ प्राईम टॉवर,
ओखला फेज-1, तेहखण्ड गाँव,
नई दिल्ली – 110020;
Email: nhfdc97@gmail.com **... प्रतिवादी संख्या 2**

1. परिवाद का सार –

1.1 श्री राकेश कुमार, 45% चलन दिव्यांग व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक, कठूरा शाखा, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) / राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनएफडीसी) से स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने के संदर्भ में एक अभ्यावेदन दिनांक 04.01.2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

1.2 परिवादी का कहना था कि उसके पास लोहे की उनकी निजी दुकान है जिसका संचालन वह पिछले

10 वर्षों से कर रहा है परन्तु उस दुकान में समस्त प्रकार का समान रखने हेतु धन की कमी है जिससे दुकान चलाने में परेशानी होती है। परिवादी ने पंजाब नेशनल बैंक, कठूरा शाखा, जनपद – सीतापुर / नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेन्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन से पाँच लाख रुपये का ऋण दिलाने का निवेदन किया था लेकिन बैंक ऋण देने में आनाकानी करते हैं।

2. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर –

2.1 प्रतिवादी संख्या 1 पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबन्धक ने उत्तर दिनांक 06.03.2023 प्रस्तुत कर परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया और कहा कि परिवादी ने ऋण के सम्बन्ध में बैंक शाखा में न कोई पूछताछ किया, न कोई आवेदन दिया, न ही शाखा प्रबन्धक से वार्तालाप किया और न ही परिवादी का उसके बैंक शाखा में आगमन हुआ है। शाखा प्रबन्धक ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में जाँच करने पर पता चला कि परिवादी विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर चुका है और सी०आई०आर० के आधार पर वह ऋण डिफाल्टर रह चुका है। परिवादी की वित्तीय साख संतोषजनक नहीं है और वह ऋण प्राप्ति के लिए पात्र नहीं है। भविष्य में यदि वह पात्र पाया जाता है तो उसके आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऋण प्रदान कर सकती है।

2.2 प्रतिवादी संख्या 2 नेशनल हैन्डीकैप फाइनेन्स एण्ड डिवैलपमेन्ट कारपोरेशन के महाप्रबन्धक (परियोजना) ने उत्तर दिनांक 07.03.2023 प्रस्तुत कर कहा कि उन्होंने अपने पत्र दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवादी को एन.एच.एफ.डी.सी. के योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की नजदीकी शाखा से सम्पर्क करने का अनुरोध किया था। परिवादी को यह भी बताया गया था कि यदि एन.एच.एफ.डी.सी. के योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई सामने आती है तो वे निःसंकोच एन.एच.एफ.डी.सी. से सम्पर्क कर सकते हैं।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर –

3.1 परिवादी ने प्रत्युत्तर दिनांक 30.03.2023 प्रस्तुत किया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिए उत्तर को सरासर गलत बताया और कहा कि आई०सी०आर० रिपोर्ट लगाकर प्रदिवादी बैंक अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। परिवादी ने बताया कि सन् 2014 में उन्हें एक बार इण्डियन बैंक से दो लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था जिसमें से उसे कुल एक लाख बीस हजार रुपये ही दिए गए और बाकी अस्सी हजार रुपये देने से बैंक ने मना कर दिया था। अन्ततः परिवादी को ओटीएस के माध्यम से समझौता करना पड़ा और 2019 में ऋण की अदायगी हो चुकी है। परिवादी ने यह भी कहा कि यदि बैंक दस रुपये में से केवल छः रुपये ही देगा तो डिफाल्टर की श्रेणी में तो होना ही पड़ेगा। परिवादी ने कहा कि उसका उद्यम पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या 71-0010128 है परिवादी ने इस प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई कर ऋण दिलाने के लिए अनुरोध किया।

4. सुनवाई —

इस मामले में सर्वप्रथम सुनवाई दिनांक **20.09.2024** को सुनिश्चित की गई थी परन्तु उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी और पुनः दिनांक **30.09.2024** को ऑनलाइन वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। निम्नलिखित पक्षकार / प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित थे —

क्र.स.	पक्षकार/प्रतिनिधियों के नाम	उपस्थिति का

		माध्यम
<u>परिवादी पक्ष से</u> —		
1.	श्री राकेश कुमार, परिवादी	ऑनलाइन
<u>प्रतिवादी संख्या 1 से</u> —		
1.	श्री गौरव अग्रवाल, प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कठूरा शाखा, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	ऑनलाइन
<u>प्रतिवादी संख्या 2 से</u> —		
1.	श्री मनु मिश्रा, सहायक महाप्रबन्धक, एनडीएफडीसी	ऑनलाइन

5. सुनवाई की कार्यवाही —

5.1 प्रतिवादी संख्या 1, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने कहा कि वे स्वयं परिवादी की दूकान पर जाकर परिवादी से सम्पर्क किया था। परिवादी पीएनबी का ग्राहक नहीं है क्योंकि पीएनबी में परिवादी का न बचत खाता है और न ही चालू खाता है। परिवादी की दूकान पीएनबी शाखा से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर है। तथापि परिवादी को यह सुझाव दिया गया कि वे सर्वप्रथम पीएनबी में अपना खाता खुलवाए और फिर ऋण हेतु आवेदन करें ताकि उनका सिबील स्कोर जाना जा सके और ऋण देने हेतु विचार किया जा सके।

5.2 प्रतिवादी संख्या 2, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनडीएफडीसी) के प्रतिनिधि ने कहा कि परिवादी दिवालिया अथवा दोषी है ऐसी कोई सूचना बैंक द्वारा एनडीएफडीसी को नहीं दिया गया है। फिर भी बैंक परिवादी के क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर परिवादी को ऋण देने पर विचार कर सकती है क्योंकि ऋण देने के लिए बैंकों की व्यवस्था प्रावधान अलग-अलग है। प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि इस न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर एनडीएफडीसी द्वारा परिवादी को लिखित रूप से सुझाव दिया गया था कि वे पीएनबी के अपने निकटतम शाखा से ऋण लेने हेतु सम्पर्क/आवेदन करें।

5.3 सुनवाई के दौरान परिवादी ऑन लाइन उपस्थित होते हुए भी न्यायालय को उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

6. अवलोकन एवं अनुशंसा —

6.1 सभी पक्षों को सुनने के पश्चात और फाइल पर उपलब्ध आलेखों के आधार पर न्यायालय ने परिवादी को सुझाव दिया कि वे यथाशीघ्र सर्वप्रथम अपना एक खाता परिवादी बैंक में खोलवाएँ और तत्पश्चात ऋण हेतु विधिवत और नियमानुसार परिवादी बैंक में आवेदन करें और इसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 2 को भी दें। प्रतिवादी संख्या 1 परिवादी से प्राप्त ऋण हेतु आवेदन पत्र पर परिवादी को ऋण देने हेतु विचार करेंगे और अपना उत्तर 15 दिनों के भीतर परिवादी सहित, प्रतिवादी संख्या 2 और इस न्यायालय को सूचनार्थ भेजेंगे।

6.2 तथापि प्रतिवादी के द्वारा उठाये गए कदम से असंतुष्ट होने कि स्थितिपरिवादी पुनः इस न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं।

6.3 तद्नुसार, इस परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

Digitally signed by
Rajesh Aggarwal
Date: 03-10-2024 22:20:11

(राजेश अग्रवाल)
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/Government of India
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No. CCPD/14143/1022/2023

In the Matter of —

Shri N. Feroz Khan
Regional Office, Hyderabad
REC Limited, Shivrampally,
Post NPA, Hyderabad,
Telangana – 500052
Contact No. 9884950209
Email ID : n.khan@recl.in and nfkrec@rediffmail.com **……Complainant**

Versus

The Chairman & Managing Director
REC Limited
Corporate Office,
Plot No. I-4, Sector - 29,
Gurugram, Haryana – 122001
Email ID cmd@recl.in **…...**
Respondent

1. GIST OF THE COMPLAINT:

1.1 Shri N. Firoz Khan, a person with 50% locomotor disability filed a complaint dated 25.04.2023 requesting for his transfer to the Regional Office, Chennai (Hometown) and to follow the guidelines regarding transfer and promotion of employees with disabilities.

1.2 He has submitted that he joined REC Ltd. on 28.03.20007 as an Assistant Project Engineer at the Corporate Office in New Delhi. At the time of his joining, he had requested to be posted at his hometown at the Regional Office, in Chennai. However, he was posted to the Regional Office at Thiruvananthapuram, Kerala in April 2007. Subsequently, he was transferred to the Regional Office in Bengaluru, Karnataka in October 2007 and was then transferred to the Regional Office, in Chennai in May 2008. Since, then he has been working in the Regional Office, Chennai. During the COVID-19 phase II period, he was transferred from Regional Office Chennai (Home town) to State Operation Division/Headquarters, Gurugram, Haryana vide OM dated 23.09.2021 with standing instructions to be relieved within 7 days from Regional Office Chennai. He joined duty at HQ on 03.10.2021 and made several verbal requests to top management for his transfer to his hometown.

1.3 He also submitted that there are many abled persons in REC Ltd. posted in Corporate Office/HQ/Regional Offices who have been serving in the same station for

more than 10 years even after getting promotions without change of station.

1.4 Despite expressing his difficulties being outside his hometown without family he was transferred to Regional Office/Thiruvananthapuram, Kerala State vide O.M. dated 17.06.2022 and relieved on 21.06.2022 with a direction to join duty at RO, TVM immediately. He joined RO-TVM on 22.06.2022. On 19.09.2022 he submitted a representation to the Executive Director (HR) clearly expressing the difficulties that he was facing there and requested to transfer him back to the Regional Office Chennai, due to his disability and as per the Government guidelines. He also gave another request to the Executive Director (HR) cum Grievance Redressal Officer for Persons with Disabilities on 15.12.2022. He also drew attention to the Equal Opportunity Policy of REC Ltd. as per which the following benefits are provided regarding the transfer and posting of employees with disabilities:

(a) As far as possible persons with disabilities may be exempted from rotational transfer policy/transfer.

(b) Persons with disabilities across all grades and employees who have a disabled Spouse/Child, may be provided preference in place of posting at the time of transfer/promotion subject to administrative constraints.

(c) The persons with disabilities should preferably be posted to perform such jobs they be allowed to continue performing such jobs as far as possible.

2. SUBMISSIONS OF THE RESPONDENT :

2.1 The General Manager (HR), REC Ltd vide letter dated 25.07.2023 filed a reply in the matter. He has inter-alia submitted that the Complainant had joined on 28.03.2007 as Engineer (Engg.) at the Corporate Office and subsequently posted to Regional Office Thiruvananthapuram on 16.04.2007. The Complainant was transferred and posted from Regional Office Thiruvananthapuram to Regional Office, Bangalore on 11.10.2007. Subsequently, considering the Complainant's request he was transferred and posted to Regional Office Chennai. The Complainant was working in Regional Office Chennai from 21.05.2008 to 03.10.2021 i.e., for more the 13 years. Considering his experience and the requirements at the Corporate Office he was transferred to Corporate Office Gurugram, Haryana on 04.10.2021. Considering his request for transfer to Chennai, he was accommodated in a neighboring State i.e. Kerala, Thiruvananthapuram, as the Complainant had already worked in Chennai for more than 13 years.

2.2 He further submitted that considering the organization requirement and his experience he was posted at the Regional Office Hyderabad on 15.02.2023, which is also another neighboring State to his home State and since then, he has been working in the Regional Office, Hyderabad. The medical facilities are available in plenty to the employees and their dependents at every office as they are situated in state capitals only. Unlike some other CPSUs, the REC Ltd. has a lean manpower of just around 430 and, therefore, there are challenges in manpower resources and posing the right officers at the right places in the 22 Regional and Corporate Offices. He also submitted that whenever to the extent possible, the Corporation has been very considerate and accommodative in posting and transfer.

3. SUBMISSION MADE IN THE REJOINDER :

3.1 The Complainant vide email dated 13.08.2023 filed a rejoinder in the matter and inter-alia submitted that it is clearly evident from the REC's reply that he was transferred from the Regional Office, Chennai to the Corporate Office, Gurugram, Haryana just

because he had completed 13 years of service in RO, Chennai. As per the Equal Opportunity Policy employees with disabilities may be exempted from rotational transfer policy/ transfer but it is noticed that just because he served 13 years in his hometown Chennai he was transferred to a remote location/station far away from his hometown and not due to any administration constraints.

3.2 He was transferred from Regional Office Chennai vide OM dated 23.09.2021 upon joining of Shri M. Udayakumar, General Manager (Tech.) transfer from Headquarter/SOP Division, Gurugram, Haryana to RO Chenani vide OM dated 27.08.2021.

4. COMMUNICATION REGARDING LEGAL FRAMEWORK :

4.1 After considering the submission of the parties a letter dated 18.01.2024 regarding the legal framework related to posting/transfer/retention of employees with disabilities and caregivers to dependent persons with disabilities was sent to the Chairman & Managing Director, REC Ltd. The General Manager (HR), REC vide letter dated 01.02.2024 has inter-alia informed that the request of the Complainant for transfer to the Regional Office, Chennai is being examined and will be deliberated accordingly as per the organizational requirements.

5. ADDITIONAL SUBMISSION OF COMPLAINANT :

5.1 The Complainant vide his letter dated 03.10.2024 has now expressed his willingness to withdraw his complaint and requested to drop the case.

6. OBSERVATION & RECOMMENDATION

6.1 Considering the fact that the Complainant has withdrawn his Complaint, no further action lies in the matter. Accordingly, the case is disposed of with the approval of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

Digitally signed by
Praveen Prakash Ambashta
Date: 03-10-2024 16:46:26

(Praveen Prakash Ambahsta)

Dy. Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No. 14220/1014/2023

In the matter of —

Dr. Sonam Kumar Pruthi,
R/o H. No. A-1/363, 2nd Floor,
Paschim Vihar, Punjabi Bagh,
West Delhi District,
Delhi - 110063
Email: sonam_manipal@yahoo.com
Contact: 9718978729 **... Complainant**

Versus

(1) The Secretary,
Health and Family Welfare Department,
Government of NCT of Delhi,
9th Level, A-Wing, IP Extension,
Delhi Secretariat,
New Delhi - 110002
Email: pshealth@nic.in **... Respondent No.1**

(2) The Secretary,
Union Public Service Commission,
Shahjahan Road,
New Delhi - 10069
Email: secyoffice-upsc@gov.in **... Respondent No.2**

1. Gist of the Complainant:

1 . 1 Dr Sonam Kumar Pruthi, MBBS, MD, Complainant, a person with 41% Locomotor Disability (Spinal Deformity - Ankylosing Spondylosis with Stiffness of

Hip Joint), is working as Consultant Pathologist in Delhi filed a complaint dated 17.05.2023 regarding non-availability of Spine Deformity as a sub-category of disability in the Online Recruitment Application (ORA) published by UPSC under Vacancy No. 23050909113.

1.2 He submitted that he was trying to contact the UPSC with the landline numbers available on the internet. However, there has been no positive response from their end. He also submitted that after the order dated 18.04.2022 passed by the Hon'ble High Court of Delhi, DEPwD vide notification dated 29.08.2022 had clarified the position in respect of persons with Spine Injury (SI)/Spine Deformity (SD) by classifying them into two categories (i) persons with SI/SD without any associated neurological/limb dysfunction and (ii) persons with SI/SD with associated neurological/limb dysfunction. These categories should be incorporated under Locomotor disabilities.

1.3 He requested that the UPSC be asked to modify the subcategory of locomotor disability so that he should apply for the post as the last date was 01.06.2023 or else UPSC should come up with an alternative so that he can fill the application form to get benefits of PwDs.

2. Reply filed by the Respondents:

2.1 The Deputy Secretary (HR-Med), Health & Family Welfare Department, Govt. of NCT of Delhi (Respondent No.1) filed a reply dated 11.08.2023 and inter-alia submitted that the requisition to UPSC for filling the 234 Posts of Medical Officer was sent. Out of 234 posts, 41 posts are reserved for candidates with disabilities. The suitability of these posts of Medical Officers for persons with disabilities has been decided as per the Gazette Notification dated 07.01.2021 issued by the Government of India. As per the said notification, the post of Medical Officer is suitable for OA/OL/BL/LC/Dw/AAV and SLD having functional requirements such as S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H and C. Accordingly, the post of Medical Officers was identified suitable for persons with disabilities and requisition was accepted by UPSC. Thus, the standard guidelines were followed by their department for suitability of the post to persons with disabilities and there was no discrepancy as alleged by the Complainant.

2.2 No Response was received from UPSC (Respondent No.2) despite the issuance of notice dated 26.06.2023 followed by a reminder dated 14.08.2023.

3. Rejoinder submitted by Complainant:

3.1 The Complainant filed rejoinders dated 15.10.2023 & 20.03.2023 and expressed his satisfaction to the reply filed by the Respondents. The Complainant submitted that he had applied for the post ibid, and after having discussion with UPSC personnel on call, the Complainant was asked to submit the application with different subcategory of PwD other than the one which the Complainant have. The UPSC accepted his application. The Complainant further submitted that he does not want any further action in this case, and it may be disposed of.

4. **Observation :**

4.1 The Complainant vide email dated 20.03.2024 has shown his satisfaction with the action of UPSC and requested that he doesn't want further action in the matter. In light of the above, no further intervention is required in the matter.

4.2. Accordingly, the case is disposed of with the approval of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

Digitally signed by
Praveen Prakash Ambashta
Date: 30-09-2024 11:49:17

(P. P. Ambashta)
Dy. Chief Commissioner

न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment
भारत सरकार/Government of India
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

परिवाद संख्या **14456/1024/2023**

श्री बावचंदभाई प्रेमजीभाई कुचा,
स्थल : 1/102, नर्मदा तख्तेश्वर रेसड़ेंची,
जीएमडीसी कॉलोनी के पास,
भरतनगर, भावनगर 364002 (गुजरात)
इमेल – bavchandkucha1984@gmail.com **... परिवादी**

बनाम

(1) सचिव,
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
256, रेल भवन, रायसीना मार्ग,
नई दिल्ली – 110001
इमेल : secyrb@rb.railnet.gov.in **... प्रतिवादी (1)**

(2) महाप्रबन्धक,
पश्चिमी रेलवे,
प्रथम तल, जी.एल.ओ. भवन,
मुख्यालय, चर्चगेट,
मुम्बई 400020
इमेल : gm@wr.railnet.gov.in **... प्रतिवादी (2)**

1. परिवाद का सार —

1.1 श्री बावचंदभाई प्रेमजी भाई कूचा, 80% चलन दिव्यांग पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि से इंकार करने सम्बन्धित एक अभ्यावेदन दिनांक 29.08.2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

1.2 परिवादी ने कहा कि वे पश्चिम रेलवे भावनगर के भंडार डिपो में प्रो. लिपिक के पद पर कार्यरत

हैं। वर्ष 2019 में रेलवे कि विभागीय परीक्षा में कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी और तत्पश्चात् टंकण परीक्षा में (जो कि तीन प्रयत्नों में उत्तीर्ण होना था) किन्तु उत्तीर्ण नहीं हुए।

1.3 परिवादी ने आरोप लगाया कि दिव्यांग कर्मचारी को प्रतिवादी द्वारा पदोन्नति में समान अवसर नहीं दिया गया और उनकी पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया जिससे वर्ष 2022 से 2027 तक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गयी। पुराने पद (डिपो सहायक) की वार्षिक वृद्धि पर भी रोक लगा दी गयी। कई कर्मचारी पदोन्नति के लिए परीक्षा देते हैं परन्तु सभी सफल नहीं होते और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक नहीं लगती।

1.4 परिवादी ने यह भी कहा कि दिव्यांग होने के बावजूद उनसे अधिक कार्य करवाया जाता रहा है और वे मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। उनके कनिष्ठ कर्मचारी उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हे आर्थिक नुक्सान हो रहा है। परिवादी ने अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना की।

2. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उत्तर ——

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2023 को प्रतिवादीगण को एक नोटिस जारी कर परिवादी के अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर टिप्पणी माँगी गई थी। अंतिम अनुस्मारक दिनांक 11.10.2023 को भेजे जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3. सुनवाई :

3.1 इस मामले में ऑनलाइन सुनवाई 20.09.2024 को निर्धारित की गई थी । सुनवाई के दौरान निम्नलिखित पक्ष उपस्थित थे:

श्री बावचंदभाई प्रेमजीभाई कुचा	-	शिकायतकर्ता
मिस उषा चट्टोपाध्याय, JDE (N),	-	प्रतिवादी सं० 1
श्री सौम्यदीप सिंह, Dy. CMM/SBI	-	प्रतिवादी सं० 2

3.2 मुख्य आयुक्त ने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके कार्यालय द्वारा उनकी वेतन वृद्धि और प्रमोशन रोकने का आदेश दिया गया है | क्या शिकायतकर्ता ने उसकी प्रति संलग्न की है | किन कारणों से कोई आदेश निकला होगा, कारण बताओ नोटिस, कोई जांच हुई होगी | एक तरफ तो शिकायतकर्ता का कहना है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए पर टंकण में 3 प्रयासों के बाद भी उत्तीर्ण नहीं हुए | इसलिए आपको पदोंनीति नहीं मिली | दुसरा मुद्दा यह है कि आप टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए इसलिए आपकी वेतन वृद्धि रोक दी |

<u>शिकायतकर्ता की दलीलें:</u>

3.3 शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका वार्षिक वृद्धि बंद कर दी गयी है और उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया है | उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्मिक एवं परीक्षण विभाग के आदेश दिनांक 1992 एवं 2017 की प्रतियाँ भी इस न्यायालय को भेजी है | उनका कहना है कि करोना की वजह से वह टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए | रेलवे बोर्ड के आदेश में भी टंकण में छुट का वर्णन है, पर वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे | परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण उनकी वेतन वृद्धि एवं नियमित वृद्धि भी रोक दी गयी

|

<u>उत्तरदाताओं का प्रस्तुतिकरण :</u>

3.4 प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिनिधि का कहना है कि जब ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाते है तो एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है , जो कि शिकायतकर्ता ने की | उसके पश्चात इन्हें टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 03 मौके दिए जाते है | पहले टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में उन्हें वापस ग्रुप डी में भेज दिया जाता था | बाद में नीति आई कि अगर कोई व्यक्ति टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेगा तो 08 साल तक उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाए | वर्तमान में शिकायतकर्ता सहायक डिपो सहाय (ADS) के पद पर कार्यरत है, जोकि एक ग्रुप डी पोस्ट है | अगर यह टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते तो वह लेवल 1 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोमोट होते |

3.5 उनका कहना है कि अब जो भी कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहे है उनमे से किसी को भी वापस ग्रुप डी में नहीं भेजा जाता सिर्फ उनका वेतन वृद्धि रोक दिया जाता है | उन्होंने कहा कि यधपि यह नीति सार्वभौमिक है एवं सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू है परन्तु दिव्यान्जनो के लिए एक छुट है | यदि किसी दिव्यान्जन के पास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है कि वह दिव्यान्गता के कारण टाइपिंग नहीं कर सकता तो उसे छुट मिल सकती है | शिकायकर्ता भावनगर में कार्यरत है | शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि का कहना है कि उनका कार्यालय साबरमती में है और उनके अधीन भावनगर, अहमदाबाद, राजकोट और साबरमती कार्यालय आते है | उनके कार्यालय में उनके पास एक दिव्यांग कर्मचारी है, जिन्हें मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर टंकण परीक्षा में छुट दी गयी है |

4. <u>अवलोकन और सिफारिशें :</u>

4.1 दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह पाया गया कि मामले में शिकायतकर्ता के साथ दिव्यान्गता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है | नीति सार्वभौमिक है एवं सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर एक समान लागू होती है | इस नीति में भी दिव्यान्जन को छुट दी गयी है कि यदि कोई दिव्यान्जन अपनी दिव्यान्गता के कारण टाइपिंग करने में असमर्थ है एवं उसके पास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है जोकि यह प्रमाणित करता है कि वह अपनी दिव्यान्गता के कारण टाइपिंग करने में असमर्थ है तो उसे छुट दी जाती है |

4.2 यह न्यायालय अनुशंसा करता है कि यदि शिकायतकर्ता को मेडिकल बोर्ड से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है कि वह अपनी विकलांगता के कारण टाइप करने में असमर्थ है, तो प्रतिवादी उस प्रमाण-पत्र पर विचार करें तथा मामले में नियमानुसार उचित कार्रवाई कर सकता है । प्रतिवादी इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजे |

4.3 तद्नुसार मामले का निपटान किया जाता है |

Digitally signed by
Rajesh Aggarwal
Date: 26-10-2024 12:51:16

(राजेश अग्रवाल)

मुख्य आयुक्त

सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No. 15629/1141/2024

In the matter of —

Suo-motu cognizance of spate of deaths at the shelter home – "Asha Kiran", Delhi run by Social Welfare Department, Govt. of NCT of Delhi

Versus

Respondent No. 1	**Respondent No. 2**
The Secretary, Social Welfare Department, Government of NCT of Delhi, 7th Floor, MSO Building, ITO, I.P. Estate, New Delhi – 110002 Email: pssw@nic.in	The Administrator, Asha Kiran Complex, Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi, Avantika, Rohini, Sector-1, Delhi – 110085

1. Gist of the Complaint:

1.1 A news item published in the daily, The Times of India on 02.08.2024 under the headlines: "Deaths at Delhi govt's shelter home spike in July, spark alarm". The news stated as under:

> *"NEW DELHI: A spate of deaths in the second fortnight of July this year at Asha Kiran in Rohini - the only Delhi govt-run facility for people with mental impairment in the capital - has caused alarm and revived allegations of neglect and poor living conditions that have haunted it in the past. According to sources and documents of Asha Kiran's medical care unit seen by TOI, 12 inmates, most of them women, have died between July 15 and July 31. The*

symptoms of the patients were similar as the toll went up - loose motion and vomiting. The bodies of inmates who pass away and patients who cannot be treated at the facility are usually sent to Dr Baba Saheb Ambedkar Hospital, which is just 2km away from the shelter home. According to sources in the forensic department of the hospital who wish to remain anonymous, the list of those who died includes 10 women and two men. Only one body was received for autopsy between July 1 and July 15, indicating there was a sudden surge in the next fortnight which needs to be investigated. In fact, several other inmates are learnt to be undergoing treatment at the hospital. Going by the data of the medical care unit, in July, 54 inmates were sent outside the facility for treatment, more than usual. "The initial case summary of many of the inmates showed symptoms of loose stools (diarrhoea) but only the final FSL report will determine the cause of death," said a source.

Water samples being tested after deaths at shelter home.

Speaking to TOI, the director of Delhi govt's social welfare department, Anjali Sehrawat, acknowledged that there had been a surge in the number of deaths at Asha Kiran but denied that it was as high as 12 in the second fortnight of the past month. She, however, did not provide any figure. "There has been a surge in the deaths of inmates but that can be attributed to multiple things," said Sehrawat.

Confirming the symptoms of the inmates who were affected, Sehrawat said: "After July 15, we did receive a higher number of complaints of the said symptoms among the inmates following which we have launched an investigation. However, it has to be kept in mind that it was quite humid and hot in the last week and the inmates are also suffering from severe illnesses."

"Integrated Disease Surveillance Programme has taken water samples and will be giving us a report after confirming if there was any water contamination. Further, we will also investigate the allegations of outside food being provided to children. We will also check the postmortem reports once they are out and see if there are any signs of food poisoning which could have led to the death of the inmates. The reports will be released in the following week,"

she said.

The data from Asha Kiran's medical care centre shows that since Jan 2024, every month, only two to three deaths had been reported. It was only in the month of July that the number of deaths saw a sharp increase.

TOI has the month-wise break-up.

"We are denying that a higher number of patients were sent outside in the month of July. However, consider it a good thing that more inmates are being sent for expert examination as our centre at Asha Kiran has only preliminary check-up facilities," said Sehrawat.

The shelter home, run by the social welfare department, was established in 1989 and has a capacity of housing around 500 inmates — it has 1,000 as of now. The overcrowded facility has 10 dormitories for men and 10 for women. It has around six doctors and about 17 nurses to take care of the patients.

Asha Kiran is not new to controversy. The Comptroller and Auditor General (CAG) had red-flagged its functioning n a 2015 report. It had observed that the facility was "over-burdened", illequipped for medical emergencies and short on staff. In fact, its capacity during the CAG review was 350 and increased later.

The report had highlighted that a total of 148 deaths had occurred during 2009-14. It also found "slackness on the part of the department towards decongestion of the Asha Kiran complex". In 2017, Delhi Commission for Women had also come out with a report which stated that the facility was in a poor state.

Delhi govt didn't reply to queries sent on Asha Kiran. Incidentally, the social welfare portfolio has not been reassigned after Raaj Kumar Anand quit from both govt and party in April and later joined BJP."

2. Notice issued to the Respondents:

In exercise of the powers conferred under sections 75 & 77 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 [hereinafter referred to as "the Act"], a suo-motu cognizance was taken in the aforesaid news item;

and a notice dated 02.08.2024 was issued to the Respondents for furnishing their comments to this Court within 07 days.

3. Reply filed by the Respondents:

3.1 The Deputy Director (Disabilities), Social Welfare Department, GNCTD vide email dated 09.08.2024 furnished a preliminary report containing 20 pages relating to the year 2018. However, no comments were filed on the news item published and the notice issued by this Court.

3.2 No reply was filed by the “Asha Kiran”.

4. Hearing:

A hearing was scheduled on 09.10.2024 but due to administrative exigency, the same was adjourned and conducted on **21.10.2024** online through video conferencing at the Office of Secretary, Room No. 529, B-III Wing, Antyodaya Bhawan, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment. The following persons were present during the hearing:

Sl. No.	Name of the parties/ Representatives	Mode of Presence
	From Respondent No.1:	
1.	None appeared	--
	From Respondent No.2:	
1.	Mr. Pankaj Kumar Verma, Dy. Director, Asha Kiran	Online

5. Proceedings of Hearing:

5.1 During the hearing the representative of Respondent No.2 affirmed that in July 2024 a total of 14 deaths took place in the Asha Kiran complex. The present matter is already pending before the Hon’ble High Court of Delhi and the next hearing is scheduled on 12.11.2024. On the directions of the Hon’ble High Court of Delhi, a building of MCD in Narela Delhi which was earlier used as a nursing college and hostel, has been given to the Social Welfare Department, GNCT Delhi for decongestion of the existing homes. The situation has now significantly improved. The BMI of the women and children of the Home is being checked regularly, vacant posts of staff and special educators, clinical psychologists, and physiotherapists have been filled up, and air conditioners have been installed on the first floor of the

building. Almost 70-80 residents have been shifted to other homes, namely Asha Deep and Asha Jyoti. The concerned District. Magistrate has been appointed as ex officio Administrator of the Home in their respective district.

6. Observations & Recommendations:

After hearing the representative of the respondent, this Court is inclined to conclude that further intervention in this case is not warranted in light of the fact that the matter is already pending before the Hon'ble High Court of Delhi. As such, the case is disposed of.

Digitally signed by
Rajesh Aggarwal
Date: 25-10-2024 14:11:24

(Rajesh Aggarwal)
Chief Commissioner